रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 20 मार्च, 1985/29 फाल्गुन, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 19 मार्च, 1985

संख्या 1-27/85-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 (1985 का विधेयक संख्यांक 1) जो दिनांक

19 मार्च, 1985 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करन हेतु प्रेषित किया जाता है ।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव ।

1985 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धन राशि के भुगतान की स्वीकृति और उनके विनियोग हेतु—

विधेयक।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1985 कहलायेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1984-85 वर्ष के लिए 1,07,07,37,717 रुपये की और राशि निकालना।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां जिनका जोड़ एक अरब, सात करोड़, सात लाख, सैंतीस हजार, सात सौ सतरह रुपए आता है निकाली जाए और उनका वित्तीय वर्ष 1984-85 की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु उपयोग किया जाए।

विनियोग।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को निकालने और उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धन राशियों का विनियोग, धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जायेगा।

अनुसूची

(देखिये धारा 2 तथा 3)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनाधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रु0	रु0	रु0
1.	विधान सभा तथा निर्वाचन	(राजस्व)	50,000	—	50,000
2.	राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	16,53,000	3,28,000	19,81,000
3.	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	22,56,000	12,78,250	35,34,250
4.	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	94,03,000	7,06,655	1,01,09,655
		(पूंजी)	3,13,000	—	3,13,000
5.	भू-राजस्व	(राजस्व)	1,24,55,000	2,670	1,24,57,670
6.	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	5,38,500	2,711	5,41,211
7.	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	(राजस्व)	1,75,61,400	4,584	1,75,65,984
8.	शिक्षा, कला तथा संस्कृति	(राजस्व)	1,69,46,400	3,80,000	1,73,26,400
	एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	(पूंजी)	21,82,000	1,31,982	23,13,982
9.	चिकित्सा और परिवार नियोजन	(राजस्व)	78,30,000	—	78,30,000
		(पूंजी)	—	1,90,516	1,90,516
10.	लोक निर्माण	(राजस्व)	86,24,000	7,927	86,31,927
		(पूंजी)	20,70,000	—	20,70,000
11.	कृषि	(राजस्व)	3,03,06,000	2,44,446	3,05,50,446
		(पूंजी)	30,71,000	52,557	31,23,557
12.	लघु सिंचाई	(राजस्व)	34,50,000	—	34,50,000
		(पूंजी)	27,00,000	—	27,00,000
13.	भूमि तथा जल संरक्षण	(राजस्व)	67,87,000	—	67,87,000
		(पूंजी)	1,50,000	—	1,50,000
14.	पशुपालन तथा दुग्ध विकास	(राजस्व)	75,65,000	65,980	76,30,980
15.	मत्स्य	(राजस्व)	4,59,000	—	4,59,000
16.	वन	(पूंजी)	10,00,000	—	10,00,000
17.	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	2,53,25,000	—	2,53,25,000
		(पूंजी)	43,33,881	10,09,840	53,43,721
18.	सप्लाई, उद्योग तथा खनिज	(राजस्व)	50,22,000	—	50,22,000
		(पूंजी)	25,00,000	—	25,00,000
19.	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेलें	(राजस्व)	19,40,000	—	19,40,000
20.	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता	(राजस्व)	1,82,33,000	553	1,82,33,553
	एवं जल आपूर्ति	(पूंजी)	7,61,35,000	—	7,61,35,000

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
21.	सामुदायिक विकास	(राजस्व)	6,64,69,000	250	6,64,69,250
		(पूंजी)	—	48,936	48,936
22.	सहकारिता	(राजस्व)	17,98,000	—	17,98,000
		(पूंजी)	78,15,000	—	78,15,000
23.	खाद्य एवं पोषाहार	(राजस्व)	1,000	—	1,000
		(पूंजी)	—	438	438
24.	जल तथा विद्युत विकास	(राजस्व)	1,43,10,000	—	1,43,10,000
		(पूंजी)	11,15,06,000	—	11,15,06,000
25.	सिंचाई, नावचालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	10,00,000	—	10,00,000
		(पूंजी)	5,00,000	—	5,00,000
26.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(राजस्व)	20,00,000	—	20,00,000
		(पूंजी)	3,30,000	—	3,30,000
27.	सड़क परिवहन	(पूंजी)	1,000	—	1,000
28.	पर्यटन	(पूंजी)	4,87,000	—	4,87,000
29.	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	20,000	—	20,000
30.	आवास	(राजस्व)	5,00,000	—	5,00,000
		(पूंजी)	1,21,60,000	—	1,21,60,000
31.	नगर विकास	(राजस्व)	27,81,000	—	27,81,000
		(पूंजी)	30,00,000	—	30,00,000
32.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	(राजस्व)	1,10,93,000	2,62,900	1,13,55,900
		(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000
33.	वित्त	(राजस्व)	33,77,000	1,29,42,041	1,63,19,041
		(पूंजी)	—	51,23,90,000	51,23,90,000
34.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	15,00,000	—	15,00,000
35.	जनजातीय विकास	(राजस्व)	2,09,37,300	—	2,09,37,300
		(पूंजी)	32,42,000	—	32,42,000
		जोड़	54,06,86,481	53,00,51,236	1,07,07,37,717
		राजस्व	30,06,90,600	1,62,26,967	31,69,17,567
		पूंजी	23,99,95,881	51,38,24,269	75,38,20,150

उद्देश्य तथा कारणों का कथन

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 की धारा (1) के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

शिमला :
19 मार्च, 1985.

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिन-ए-सी-(2) 31/84]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने तथा उस पर सभा द्वारा विचार किये जाने का अभिस्ताव किया है।

[*Authorised English text of the Himachal Pradesh Viniyog Vidheyak*, 1985, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

Bill No. 1 of 1985

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1985

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the year ending on the 31st day of March, 1985.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1985.

Issue of a further sum of Rs. 1,07,07,37,717 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the year 1984-85.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of one hundred seven crores, seven lakhs, thirty-seven thousand, seven hundred and seventeen rupees towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year 1984-85 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 & 3)

1	2	3		
No. of Demand	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Vidhan Sabha and Elections (Revenue)	50,000	—	50,000
2.	Governor and Council of Ministers (Revenue)	16,53,000	3,28,000	19,81,000
3.	Administration of Justice (Revenue)	22,56,000	12,78,250	35,34,250
4.	General Administration (Revenue)	94,03,000	7,06,655	1,01,09,655
	(Capital)	3,13,000	—	3,13,000
5.	Land Revenue (Revenue)	1,24,55,000	2,670	1,24,57,670
6.	Excise and Taxation (Revenue)	5,38,500	2,711	5,41,211
7.	Police and Fire Protection (Revenue)	1,75,61,400	4,584	1,75,65,984
8.	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research (Revenue)	1,69,46,400	3,80,000	1,73,26,400
	(Capital)	21,82,000	1,31,982	23,13,982
9.	Medical and Family Planning (Revenue)	78,30,000	—	78,30,000
	(Capital)	—	1,90,516	1,90,516
10.	Public Works (Revenue)	86,24,000	7,927	86,31,927
	(Capital)	20,70,000	—	20,70,000
11.	Agriculture (Revenue)	3,03,06,000	2,44,446	3,05,50,446
	(Capital)	30,71,000	52,557	31,23,557
12.	Minor Irrigation (Revenue)	34,50,000	—	34,50,000
	(Capital)	27,00,000	—	27,00,000
13.	Soil and Water Conservation (Revenue)	67,87,000	—	67,87,000
	(Capital)	1,50,000	—	1,50,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
14.	Animal Husbandry and Dairy Development (Revenue)	75,65,000	65,980	76,30,980
15.	Fisheries (Revenue)	4,59,000	—	4,59,000
16.	Forests (Capital)	10,00,000	—	10,00,000
17.	Roads and Bridges (Revenue)	2,53,25,000	—	2,53,25,000
	(Capital)	43,33,881	10,09,840	53,43,721
18.	Supplies, Industries and Minerals (Revenue)	50,22,000	—	50,22,000
	(Capital)	25,00,000	—	25,00,000
19.	Social Security, Welfare and Jails (Revenue)	19,40,000	—	19,40,000
20.	Public Health, Sanitation and Water Supply (Revenue)	1,82,33,000	553	1,82,33,553
	(Capital)	7,61,35,000	—	7,61,35,000
21.	Community Development (Revenue)	6,64,69,000	250	6,64,69,250
	(Capital)	—	48,936	48,936
22.	Co-operation (Revenue)	17,98,000	—	17,98,000
	(Capital)	78,15,000	—	78,15,000
23.	Food & Nutrition (Revenue)	1,000	—	1,000
	(Capital)	—	438	438
24.	Water and Power Development (Revenue)	1,43,10,000	—	1,43,10,000
	(Capital)	11,15,06,000	—	11,15,06,000
25.	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control (Revenue)	10,00,000	—	10,00,000
	(Capital)	5,00,000	—	5,00,000
26.	Stationery and Printing (Revenue)	20,00,000	—	20,00,000
	(Capital)	3,30,000	—	3,30,000
27.	Road Transport (Capital)	1,000	—	1,000
28.	Tourism (Capital)	4,87,000	—	4,87,000
29.	Labcur and Employment (Revenue)	20,000	—	20,000
30.	Housing (Revenue)	5,00,000	—	5,00,000
	(Capital)	1,21,60,000	—	1,21,60,000
31.	Urban Development (Revenue)	27,81,000	—	27,81,000
	(Capital)	30,00,000	—	30,00,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
32. Other Administrative Services				
	(Revenue)	1,10,93,000	2,62,900	1,13,55,900
	(Capital)	50,00,000	—	50,00,000
33. Finance	(Revenue)	33,77,000	1,29,42,041	1,63,19,041
	(Capital)	—	51,23,90,000	51,23,90,000
34. Loans to Government Servants				
	(Capital)	15,00,000	—	15,00,000
35. Tribal Development				
	(Revenue)	2,09,37,300	—	2,09,37,300
	(Capital)	32,42,000	—	32,42,000
Total		54,06,86,481	53,00,51,236	1,07,07,37,717
	(Revenue)	30,06,90,600	1,62,26,967	31,69,17,567
	(Capital)	23,99,95,881	51,38,24,269	75,38,20,150

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1984-85.

SHIMLA:
The 19th March, 1985.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(2) 31/84]

The Governor, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1985, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction, in and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 19 मार्च, 1985

संख्या 1-28/85-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 (1985 का विधेयक संख्यांक 2) जो दिनांक 19 मार्च, 1985 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव ।

1985 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 1985-86 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धन राशियां चुकाने और उनका विनियोग करने हेतु—

विधेयक ।

यह भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 कहलाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वर्ष 1985-86 के लिए 1,59,32,74,000 रुपये की राशि निकालना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां, जिनका जोड़ एक अरब, उनासठ करोड़, बत्तीस लाख, चौहत्तर हज़ार रुपये है निकाली जाए और वित्तीय वर्ष 1985-86 के पहले तीन मास की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु, उपयोग किया जाए ।

विनियोग

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन धन राशियों को निकालने और उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धन राशियों का विनियोग धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जायेगा ।

अनुसूची

(देखिए धारायें 2 और 3)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनाधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा तथा निर्वाचन	(राजस्व)	31,57,000	42,000	31,99,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	10,84,000	4,61,000	15,45,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	48,88,000	13,32,000	62,20,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	2,43,06,000	6,44,000	2,49,50,000
		(पूंजी)	18,000	—	18,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	1,79,48,000	—	1,79,48,000
		(पूंजी)	2,00,000	—	2,00,000
6	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	59,15,000	—	59,15,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	(राजस्व)	3,84,56,000	—	3,84,56,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	(राजस्व)	17,43,76,000	—	17,43,76,000
		(पूंजी)	13,71,000	—	13,71,000
		(राजस्व)	5,83,90,000	—	5,83,90,000
9	चिकित्सा और परिवार नियोजन	(पूंजी)	45,54,000	—	45,54,000
		(राजस्व)	8,73,73,000	—	8,73,73,000
10	लोक निर्माण	(पूंजी)	50,83,000	—	50,83,000
		(राजस्व)	4,94,78,000	—	4,94,78,000
11	कृषि	(पूंजी)	1,32,58,000	—	1,32,58,000
		(राजस्व)	2,68,95,000	—	2,68,95,000
12	लघु सिंचाई	(पूंजी)	42,65,000	—	42,65,000
		(राजस्व)	1,59,93,000	—	1,59,93,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(पूंजी)	10,87,000	—	10,87,000
		(राजस्व)	1,57,46,000	—	1,57,46,000
14	पशुपालन तथा दुग्ध विकास	(पूंजी)	15,05,000	—	15,05,000
		(राजस्व)	14,30,000	—	14,30,000
15	मत्स्य	(पूंजी)	7,41,000	—	7,41,000
		(राजस्व)	4,31,48,000	—	4,31,48,000
16	वन	(पूंजी)	12,50,000	—	12,50,000
		(राजस्व)	2,78,50,000	—	2,78,50,000
17	सड़कें तथा पुल	(पूंजी)	6,64,17,000	—	6,64,17,000
		(राजस्व)	2,37,31,000	—	2,37,31,000
18	सप्लाई, उद्योग तथा खनिज	(पूंजी)	52,00,000	—	52,00,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेलें	(राजस्व)	2,28,84,000	—	2,28,84,000
		(पूंजी)	17,42,000	—	17,42,000
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	(राजस्व)	7,62,83,000	—	7,62,83,000
		(पूंजी)	1,73,50,000	—	1,73,50,000
21	सामुदायिक विकास	(राजस्व)	3,98,09,000	—	3,98,09,000
		(पूंजी)	96,000	—	96,000
22	सहकारिता	(राजस्व)	66,72,000	—	66,72,000
		(पूंजी)	58,60,000	—	58,60,000
23	खाद्य एवं पोषाहार	(राजस्व)	89,86,000	—	89,86,000
		(पूंजी)	2,16,00,000	—	2,16,00,000
24	जल तथा विद्युत विकास	(राजस्व)	51,50,000	—	51,50,000
		(पूंजी)	12,72,12,000	—	12,72,12,000
25	सिंचाई, नाव चालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	44,50,000	—	44,50,000
		(पूंजी)	40,37,000	—	40,37,000
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(राजस्व)	55,17,000	—	55,17,000
		(पूंजी)	7,50,000	—	7,50,000
27	सड़क परिवहन	(राजस्व)	7,44,000	—	7,44,000
		(पूंजी)	55,22,000	—	55,22,000
28	पर्यटन	(राजस्व)	12,07,000	—	12,07,000
		(पूंजी)	27,81,000	—	27,81,000
29	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	45,49,000	—	45,49,000
		(पूंजी)	2,00,000	—	2,00,000
30	आवास	(राजस्व)	17,45,000	—	17,45,000
		(पूंजी)	41,07,000	—	41,07,000
31	नगर विकास	(राजस्व)	1,09,12,000	—	1,09,12,000
		(पूंजी)	5,00,000	—	5,00,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	(राजस्व)	2,85,67,000	—	2,85,67,000
		(पूंजी)	4,24,000	—	4,24,000
33	वित्त	(राजस्व)	2,67,87,000	8,17,47,000	10,85,34,000
		(पूंजी)	—	25,57,12,000	25,57,12,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	62,25,000	—	62,25,000
35	जनजातीय विकास	(राजस्व)	6,27,01,000	—	6,27,01,000
		(पूंजी)	2,28,84,000	—	2,28,84,000
	कुल जोड़	. .	1,25,33,36,000	33,99,38,000	1,59,32,74,000

उद्देश्य तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1985-86 के पहले तीन मास के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 व 204 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा न होने तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 की धारा (1) व अनुच्छेद 206 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है । मांगी गई राशि म वर्ष 1985-86 की नई स्कीमों के प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
19 मार्च, 1985.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिनए-सी (1) 26/84]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने तथा उस पर सभा के विचार हेतु अभिस्ताव किया है ।

[*Authorised English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Lekha Anudan) Vidheyak* 1985 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 2 of 1985.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1985

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 1985-86.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985.

Withdrawal of Rs. 1,59,32,74,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1985-86.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of one hundred fifty-nine crores, thirty-two lakhs and seventy-four thousand rupees towards defraying several charges which will come in course of payment during the first three months of the financial year 1985-86 in respect of the services specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections	(Revenue)	31,57,000	42,000	31,99,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	10,84,000	4,61,000	15,45,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	48,88,000	13,32,000	62,20,000
4	General Administration	(Revenue)	2,43,06,000	6,44,000	2,49,50,000
		(Capital)	18,000	—	18,000
5	Land Revenue	(Revenue)	1,79,48,000	—	1,79,48,000
		(Capital)	2,00,000	—	2,00,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	59,15,000	—	59,15,000
7	Police and Fire Protection	(Revenue)	3,84,56,000	—	3,84,56,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	(Revenue)	17,43,76,000	—	17,43,76,000
		(Capital)	13,71,000	—	13,71,000
9	Medical and Family Planning	(Revenue)	5,83,90,000	—	5,83,90,000
		(Capital)	45,54,000	—	45,54,000
10	Public Works	(Revenue)	8,73,73,000	—	8,73,73,000
		(Capital)	50,83,000	—	50,83,000
11	Agriculture	(Revenue)	4,94,78,000	—	4,94,78,000
		(Capital)	1,32,58,000	—	1,32,58,000
12	Minor Irrigation	(Revenue)	2,68,95,000	—	2,68,95,000
		(Capital)	42,65,000	—	42,65,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	1,59,93,000	—	1,59,93,000
		(Capital)	10,87,000	—	10,87,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	1,57,46,000	—	1,57,46,000
		(Capital)	15,05,000	—	15,05,000
15	Fisheries	(Revenue)	14,30,000	—	14,30,000
		(Capital)	7,41,000	—	7,41,000
16	Forest	(Revenue)	4,31,48,000	—	4,31,48,000
		(Capital)	12,50,000	—	12,50,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	2,78,50,000	—	2,78,50,000
		(Capital)	6,64,17,000	—	6,64,17,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	2,37,31,000	—	2,37,31,000
		(Capital)	52,00,000	—	52,00,000
19	Social Security, Welfare and Jails	(Revenue)	2,28,84,000	—	2,28,84,000
		(Capital)	17,42,000	—	17,42,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply	(Revenue)	7,62,83,000	—	7,62,83,000
		(Capital)	1,73,50,000	—	1,73,50,000
21	Community Development	(Revenue)	3,98,09,000	—	3,98,09,000
		(Capital)	96,000	—	96,000
22	Co-operation	(Revenue)	66,72,000	—	66,72,000
		(Capital)	58,60,000	—	58,60,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Food and Nutrition	(Revenue)	89,86,000	—	89,86,000
		(Capital)	2,16,00,000	—	2,16,00,000
24	Water and Power Development	(Revenue)	51,50,000	—	51,50,000
		(Capital)	12,72,12,000	—	12,72,12,000
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control	(Revenue)	44,50,000	—	44,50,000
		(Capital)	40,37,000	—	40,37,000
26	Stationery and Printing	(Revenue)	55,17,000	—	55,17,000
		(Capital)	7,50,000	—	7,50,000
27	Road Transport	(Revenue)	7,44,000	—	7,44,000
		(Capital)	55,22,000	—	55,22,000
28	Tourism	(Revenue)	12,07,000	—	12,07,000
		(Capital)	27,81,000	—	27,81,000
29	Labour and Employment	(Revenue)	45,49,000	—	45,49,000
		(Capital)	2,00,000	—	2,00,000
30	Housing	(Revenue)	17,45,000	—	17,45,000
		(Capital)	41,07,000	—	41,07,000
31	Urban Development	(Revenue)	1,09,12,000	—	1,09,12,000
		(Capital)	5,00,000	—	5,00,000
32	Other Administrative Services	(Revenue)	2,85,67,000	—	2,85,67,000
		(Capital)	4,24,000	—	4,24,000
33	Finance	(Revenue)	2,67,87,000	8,17,47,000	10,85,34,000
		(Capital)	—	25,57,12,000	25,57,12,000
34	Loans to Government Servants	(Capital)	62,25,000	—	62,25,000
35	Tribal Development	(Revenue)	6,27,01,000	—	6,27,01,000
		(Capital)	2,28,84,000	—	2,28,84,000
	Total	...	1,25,33,36,000	33,99,38,000	1,59,32,74,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the first three months of the financial year 1985-86 pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 1985-86.

SHIMLA:
The 19th March, 1985.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A.C.(1) 26/84]

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in, and consideration by, the Legislative Assembly of the said Bill.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।